*विनियमन की चुनौतियां – कुछ विचार**

एम राजेश्वर राव

देवियो, सज्जनो और विशिष्ट अतिथिगण,

इस शिखर सम्मेलन में भाग लेना वास्तव में खुशी की बात है। यह एक ऐसी सभा है जो कॉर्पोरेट जगत में जिम्मेदार प्रबंधन को विकसित करने में लगी हुई है। इस सत्र की थीम, "विनियमन की चुनौती" को ध्यान में रखते हुए, मैं विनियम और विनियमन के बदलते परिदृश्य, इसकी विकसित प्रकृति और वित्तीय क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन पर थोड़ा विचार करूंगा। बाद में, मैं इन बदलावों को प्रबंधित करने के लिए उचित विनियम बनाने में विनियामकों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों और दुविधाओं को भी रेखांकित करूंगा।

क्या हमें विनियमों की आवश्यकता है?

कई लोगों का मानना है कि न्यूनतम विनियमन, उद्यम के विकास को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इतिहास इस बात के उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कैसे न्यूनतम विनियमन के साथ उदार पर्यवेक्षण और संयमित प्रवर्तन अक्सर वित्तीय संकट का कारण बनते हैं। वास्तव में, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि धारणीय विकास के लिए खराब बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता है। जबकि एक आदर्श परिदृश्य में, 'अदृश्य शक्ति' यह सुनिश्चित करेगी कि सिस्टम न्यूनतम विनियामक निरीक्षण के साथ समष्टिगत कल्याण के लिए त्रुटिहीन रूप से कार्य करे लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में, वित्तीय क्षेत्र में अतार्किक उत्साह को नियंत्रित करने के लिए, एक ऐसे विनियामक की आवश्यकता है जो सीमाएं तय करे और मजबूत वित्तीय संस्था उन्हें लागू भी करे और इस तरह वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे।

विनियम, आमतौर पर, व्यवसाय को नियंत्रित करते हुए संस्थाओं की शुरुआत और संचलन को नियंत्रित करते हैं। यह 'प्रक्रिया' वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित संस्थाओं पर अवसर लागत लगाती है। हालाँकि, सामूहिक समष्टि कल्याण के लिए ये लागतें स्वीकार्य हैं। इसलिए, विनियमन यह सुनिश्चित करते हैं कि समग्र वित्तीय प्रणाली कुशल वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से वास्तविक क्षेत्र के लिए अपनी सहायक भूमिका निभाती है और यह स्थिर, मजबूत और उत्तरदायी बनी रहती है।

इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग उद्योग विशेष है। बैंकों की लीवरेज प्राप्त करने की अंतर्निहित क्षमता और वित्तीय प्रणाली में डोमिनोज़ प्रभाव को ट्रिगर करने की क्षमता इसे अद्वितीय बनाती है। इसके अलावा, बैंक न केवल ग्राहक की मेहनत की कमाई के संरक्षक हैं, बल्कि जन-विश्वास के भी संरक्षक हैं। यह सुनिश्चित करना आरबीआई की जिम्मेदारी है कि ग्राहकों और जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों पर जताया गया भरोसा दृढ़ता से कायम रहे।

बदलाव को प्रबंधित करना

जैसा कि हम आज वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों को देखते हैं, उन गहन संरचनात्मक बदलावों को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण हो जाता है जो वित्तीय क्षेत्र के आकार को बदल रहे हैं। इन परिवर्तनों में असंख्य कारक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी चुनौतियां हैं। ये भी जटिल, बहुआयामी मुद्दे हैं जो सूक्ष्म, अनुकूलनीय समाधान की मांग करते हैं। नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के बीच सही संतुलन बनाना हमेशा एक कठिन कार्य होता है। मैं ऐसे कुछ बदलावों के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा जिनसे हम जुड़े हुए हैं।

जलवायु परिवर्तन

हम सभी उस वैश्विक चुनौती से अवगत हैं जो जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के लिए उत्पन्न हुई है और इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। अधिक टिकाऊ, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। चूंकि समाज स्वच्छ हरित पर्यावरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की मांग करता है, इसलिए विनियामकों

---

* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा टिप्पणियां - 2 नवंबर 2023 - मुंबई - 'एक्सीलेंस एनेबलर्स' द्वारा आयोजित गेटकीपर्स ऑफ़ गवर्नेंस सम्मेलन में।

सर्व श्री दीपक राणा, विशाल कुमार प्रसाद, प्रमांशु राजपूत और प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट स्वीकार किए गए हैं।

को विनियामक ढांचे में जलवायु जोखिमों को एकीकृत करने का कार्य करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थान ऋण के प्रवाह को प्रबंधित करने के साथ-साथ अपने कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव पर भी विचार करें, एक संतुलित अधिनियम की मांग करता है और सहयोगात्मक समाधान की आवश्यकता होती है।

विनियामकों को जिस विवादास्पद प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि क्या जलवायु जोखिम एक अनूठा जोखिम है जिसे अलग से पकड़ने की आवश्यकता है और इस प्रकार स्टैंडअलोन आधार पर एक अलग ढांचे की आवश्यकता है, अथवा क्या यह क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिमों से होकर गुजरता है और इसे मौजूदा जोखिम ढांचे के एक हिस्से के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। बहस का एक और मुद्दा यह है कि क्या इन जोखिमों को स्तंभ 2 (पर्यवेक्षी समीक्षा) और स्तंभ 3 (बाजार अनुशासन और प्रकटीकरण) आवश्यकताओं के संयोजन के रूप में कैप्चर करने की आवश्यकता है या क्या सीधे स्तंभ 1 (पूंजी और तरलता) के हिस्से के रूप में जोखिम को कैप्चर करना बेहतर है।

प्रौद्योगिकीय परिवर्तन

प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से वित्त-परिदृश्य को नया आकार दे रही है और एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है जो परिचालन और ग्राहक अनुभवों को समान रूप से नया आकार दे रही है। डिजिटलीकरण ग्राहकों और ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाने, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सेवाओं को आबादी के बड़े हिस्से तक उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है।

जैसा कि हम इन तकनीकी प्रगति को अपनाते हैं, यह जरूरी है कि वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचा विकसित हो। डेटा द्वारा परिभाषित युग में, व्यक्तिगत और वित्तीय सूचना की सुरक्षा सबसे आगे आ गई है। भारत में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) हाल ही में अधिनियमित किया गया है। व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून आवश्यक था।

बड़ी मात्रा में संवेदनशील ग्राहक डेटा के संरक्षक के रूप में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। इस परिवर्तन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए, वित्तीय संस्थानों को मजबूत डेटा प्रशासन ढांचे में निवेश करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे और उनके डेटा प्रोसेसर कानून और विनियमों के पूर्ण पालन में डेटा एकत्र, संसाधित और संगृहीत करते हैं। अधिक डेटा-सचेत और 'डेटा प्रसंस्कृत' संस्थान में परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए नाजुक रास्ते पर चलने की आवश्यकता है।

डिजिटल मध्यस्थता की ओर संक्रमण

महामारी के बाद, डिजिटल ऋण और ऋण प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों के उद्भव ने भारत सहित विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से वृद्धि देखी है। हालाँकि इससे तेजी से बढ़ते डिजिटल वातावरण में ऋण के पैमाने और वेग में वृद्धि हुई है, इसने कई कारोबारी आचरण के मुद्दों को भी उठाया है।

किसी भी विनियामक के लिए विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए कि वित्तीय नवोन्मेष उचित विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को स्थापित करने के बाद ही सक्षम हों; या बाज़ारों को अपने आप विकसित होने देने के लिए एक सहज दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? अधिक उदार होने से, क्या विनियामक अप्रत्याशित कारोबारी आचरण संबंधी चिंताओं से निपटने का जोखिम उठाते हैं और चरम मामलों में, संभावित घटनाओं का सामना करते हैं और उनसे निपटते हैं जो प्रणालीगत जोखिमों को ट्रिगर कर सकते हैं जिससे ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनका अनुमान लगाना और प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है?

बहरहाल, एक विनियामक के लिए निष्क्रियता कभी भी एक विकल्प नहीं हो सकती। जिस गति से नए मॉडल, सहभागी और उत्पाद सामने आ रहे हैं, ऐसी संस्थाएं अक्सर मौजूदा विनियमों में कमियों का फायदा उठाती हैं या विनियामक ग्रे क्षेत्र में आने वाले व्यवसाय परिचालन का संचालन करती हैं, यह एक चुनौती बनी हुई है। विनियामक परिधि, आक्रामक विपणन रणनीतियों और भोले-भाले ग्राहकों के शोषण को चुनौती देने के लिए बनाए गए

व्यवसाय मॉडल यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। लेकिन, दुविधा विनियामक हस्तक्षेप की सीमा तय करने में है जो फिनटेक के नेतृत्व वाले नवोन्मेष की प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना ग्राहक दुर्व्यवहार को नियंत्रित और प्रतिबंधित करेगा।

उदाहरण के लिए, 2020 की शुरुआत में, नई प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफार्मों की ऋण गतिविधियों में बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं को दिए गए छोटे टिकट आकार के ऋण शामिल थे, जो ज्यादातर समाज के निम्न आय वर्ग जैसे छात्र, खुदरा व्यवसाय, गिग श्रमिकों, आदि में आते थे। इन उधारकर्ताओं के लिए, अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण लेने का मतलब एक खतरनाक ऋण जाल में फंसना था। स्थिति को बदतर बनाने वाली बात यह थी कि उधारकर्ताओं को ऋण लेने से पहले इतनी ऊंची ब्याज दर या शुल्क के बारे में पता भी नहीं था क्योंकि इनका पहले से खुलासा नहीं किया गया था, उनकी शिकायतें सुनने के लिए मोबाइल ऐप के अलावा कोई इंटरफ़ेस नहीं था और वसूली प्रथाएं कठोर और अपरंपरागत थीं।

हमने यह भी देखा था कि क्रेडिट अंडरराइटिंग से लेकर रिकवरी तक, हर गतिविधि को ग्राहक की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्स किया जा रहा था। डिजिटल लेंडिंग 'रेंट एन आरई' मॉडल पर काम कर रही थी, जहां फिनटेक प्लेटफॉर्म खुद को प्रमुख के रूप में प्रस्तुत करके विनियमित इकाई की ओर से सभी ऋण गतिविधियां कर रहा था। कई मामलों में, ग्राहकों को उस बैंक या एनबीएफसी के नाम के बारे में भी पता नहीं था जिसने ऋण स्वीकृत किया था।

इस मुद्दे से निपटने के लिए, विनियामक रुख डिजिटल ऋण गतिविधि को विनियमित करने और आरई (जिन्हें ऋण सेवा प्रदाता या एलएसपी के रूप में नामित किया गया था) को निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली विनियमित संस्थाओं और फिनटेक के बीच व्यवस्था पर केंद्रित हो गया है। आरबीआई के डिजिटल ऋण नियमों ने एक व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया है जिसके तहत फिनटेक विनियमित संस्थाओं के साथ सक्षम भागीदार बन सकते हैं। ये दिशानिर्देश मौजूदा दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति का मिश्रण हैं जैसे सीआईसी को रिपोर्ट करना, एलएसपी को संलग्न करने से पहले उचित परिश्रम करना आदि और कुछ नए, आरई को आधार बनाया गया है जिसके आसपास डिजिटल ऋण गतिविधियों को उनके विनियामक अनुपालन जिम्मेदारी के साथ संचालित करने की आवश्यकता होती है।

सोशल मीडिया संक्रमण

सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार की गति और दायरे में क्रांति ला दी है। सूचना साझाकरण अब तक इतना त्वरित और अबाधित कभी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अप्रमाणित अफवाहें और झूठी खबरें भी उतनी ही तेजी से फैल सकती हैं और वित्तीय संस्थानों, विशेषकर बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल की बैंकिंग उथल-पुथल ने तरलता प्रबंधन के सिद्धांतों और बैंक चलाने की प्रकृति और गति के बारे में व्यापक रूप से प्रचलित कुछ विचारों को झटका दिया है।

मार्च 2023 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग उथल-पुथल का वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस प्रकरण ने वित्तीय क्षेत्र के नियमों में वैश्विक मानकों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस प्रकरण ने दो महत्वपूर्ण सबक पेश किए हैं: पहला- ट्रस्ट कमजोरियों की धारणाओं और गलत सूचना वाली सोशल मीडिया टिप्पणियों के प्रति संवेदनशील है।

दूसरा- सोशल मीडिया और इंटरनेट बैंकिंग के युग में, जिस गति से बैंक चल रहे हैं वह अभूतपूर्व है और इसलिए, ऐसे किसी भी संकट से निपटने के लिए प्रतिक्रिया समय अब तक स्वीकार्य माने जाने वाले एक अंश तक पहुंच गया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सोशल मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार की निगरानी करने और रोकने के लिए संबंधित बैंक की क्षमता के साथ निरंतर और प्रभावी पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण हो गया है।

आरबीआई इन परिवर्तनों का प्रबंधन कैसे कर रहा है?

आरबीआई का दृष्टिकोण हमेशा वित्तीय स्थिरता विचारों के साथ संतुलन बनाते हुए नवाचारों और गतिशीलता को बढ़ावा देने और समर्थन करने का रहा है। इसलिए, मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि हम इन बदलावों को प्रबंधित करने के लिए क्या कर रहे हैं।

विनियमों का सरलीकरण

विनियामक निर्देश वित्तीय प्रणाली और संस्थानों के विकास पथ के अनुरूप समय-समय पर विकसित हुए हैं। विनियामक परिधि का भी विस्तार हुआ है क्योंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली ने नए व्यापार मॉडल, उत्पाद लाइनों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है। समय के साथ, इसके कारण अनुपालन बोझ में सहवर्ती वृद्धि के साथ कुछ नियम जटिल हो गए होंगे। इसलिए, विनियामक निर्देशों और अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए उन्हें सुव्यवस्थित / तर्कसंगत बनाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवधिक स्टॉकटेक उपयोगी है।

आरबीआई ने इस कार्य को करने और नियमों की सरलता सुनिश्चित करने के लिए 2021 में (1999 में स्थापित आरआरए 1 के बाद) विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए) की स्थापना की थी जो हमारे लिए प्राथमिकता बन गई है। मेरे विचार में, भविष्य के नियम वित्तीय प्रणाली की उभरती ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। ऐसा करने के लिए, हमने पाँच-स्तंभीय रणनीति अपनाई है -

1. सबसे पहले, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य के नियम दूरदर्शी और सक्रिय हों।
2. दूसरा, हम अपने दृष्टिकोण में फुर्तीले हो गए हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवर्तन की गति तेज हो गई है।
3. तीसरा, विनियमन बनाने के प्रति हमारा दृष्टिकोण अधिक डेटा संचालित और प्रभाव मूल्यांकन उन्मुख हो गया है। इससे, बदले में, अधिक विश्लेषणात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है और जहां भी आवश्यक हो, संक्रमण के लिए एक उपयुक्त मार्ग का प्रावधान करने में मदद मिल रही है।
4. चौथा, हम विनियमन बनाने के लिए अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हितधारकों के साथ पूर्व परामर्श हमें विविध दृष्टिकोण इकट्ठा करने और उन्हें नियमों में शामिल करने में सक्षम बनाता है। इससे नियमों का क्रियान्वयन भी बेहतर होता है।
5. पांचवां और आखिरी स्तंभ है सहयोग. हम एक सुरक्षित और लचीला वित्तीय क्षेत्र विकसित करने के लिए हितधारकों, सरकार और अन्य नियामकों और उद्योग के साथ अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं।

रिज़र्व बैंक को विभिन्न क़ानूनों के तहत अधीनस्थ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह आरबीआई पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है कि उसके निर्देश वैधानिक आदेश द्वारा निर्धारित परिधि के भीतर, भाषा में स्पष्ट, उचित और आनुपातिक हों। इसलिए, हमने अपने अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है ताकि नियमों को सरल भाषा में लिखा जा सके और विनियामक इरादे पर बेहतर स्पष्टता हो।

ग्राहक आचरण को फोकस में लाना

चीजों की पूरी योजना में, 'ग्राहक' को केंद्र में रहना चाहिए। विनियमन के दो प्राथमिक उद्देश्य अर्थात्- वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने से विनियमों की दो व्यापक श्रेणियां बनती हैं - विवेकपूर्ण विनियम और आचरण विनियम। विवेकपूर्ण विनियमन वित्तीय स्थिरता के लिए नींव बनाता है, जबकि आचरण विनियमन ग्राहक विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक आधार रखता है, साथ में हमारी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने में मदद करता है।

तदनुसार, हमारा प्रयास विनियमित संस्थाओं में जिम्मेदार आचरण विकसित करने का रहा है। हमने बैंकों से अपने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के लिए उपयुक्तता और प्रदर्शन आवश्यकताओं को डिजाइन करने के लिए कहा है। इसमें बोर्ड स्तर की निरीक्षण व्यवस्थाएं शामिल हैं जिन्हें बैंक को इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू करना होगा। जैसा कि हम आचरण आधारित नियमों के क्षेत्र में चिंताओं को दूर करने के लिए अपने दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं, मार्गदर्शक दर्शन कुछ न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं निर्धारित करना होगा, जिसमें संस्थाओं के लिए उनके आकार, आनुपातिकता और ग्राहक फोकस के आधार पर उच्च मानकों को अपनाने का विकल्प होगा। अंतिम संदेश यह है कि विनियमित

संस्थाओं को सभी ग्राहकों - बड़े या छोटे, शहरी या ग्रामीण, शिक्षित या कम शिक्षित, के साथ पारदर्शी और नैतिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए।

सिद्धांत आधारित बनाम नियम आधारित विनियम

इस बात पर बहस चल रही है कि क्या सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण बेहतर है या विनियमों के लिए नियम-आधारित दृष्टिकोण बेहतर विकल्प है। समय के विभिन्न बिंदुओं पर, एक दृष्टिकोण ने नीति निर्माताओं को दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावित किया है।

नियम-आधारित विनियमों का लाभ यह है कि यह विनियमित संस्थाओं को क्या करने की आवश्यकता है, इस पर निश्चितता और दृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करता है, और विनियामक के दृष्टिकोण से, मापने योग्य और समझाने योग्य विनियामक लक्ष्य और जिम्मेदारियां प्रदान करता है जिन्हें आसानी से निगरानी और लागू किया जा सकता है। लेकिन विनियमन के लिए एक अनुदेशात्मक दृष्टिकोण में, नियम अंततः उस इच्छित परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं जिसके लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया था, जिससे "बॉक्स टिकिंग" अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

इसके विपरीत, सिद्धांत-आधारित विनियमन एक कम्पास की तरह है, जो विनियमित संस्थाओं को एक सामान्य दिशा प्रदान करता है, बिना सटीक मार्ग निर्दिष्ट किए। सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाने और वांछित परिणामों पर जोर देने के लिए तैयार किया गया है। वे विनियमित संस्थाओं को उभरती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और नवप्रवर्तन करने की छूट देते हैं; हालाँकि, इसके लिए उन्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने और जिम्मेदार निर्णय लेने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन, अक्सर, विनियामक अपेक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए, सिद्धांत-आधारित नियमों को स्पष्टीकरण, चित्रण और मार्गदर्शन नोट्स के साथ पूरक करने की आवश्यकता होती है।

तो हम नियम-आधारित और सिद्धांत-आधारित विनियामक दृष्टिकोण की निरंतरता में कहां खड़े हैं? रिज़र्व बैंक, नीतिगत रूप से, धीरे-धीरे बैंकों को व्यापक विनियामक ढांचे के भीतर अपने व्यवसाय संचालन करने के लिए अधिक परिचालन स्वतंत्रता दे रहा है। इस प्रकार हम अपने नियमों को तेजी से सिद्धांत-आधारित बनाने की दिशा में अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं।

समान अवसर बनाए रखना

एक समान खेल का मैदान यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागी एक निष्पक्ष और सुसंगत विनियामक ढांचे के भीतर काम करते हैं जहां वित्तीय प्रणाली के संभावित जोखिम और पुरस्कार समान रूप से संतुलित होते हैं। इस बात पर व्यापक सहमति है कि प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र के लिए समान अवसर एक महत्वपूर्ण शर्त है। एक विनियामक के रूप में, हम "समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन" के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण डिजिटल ऋण, प्रथम हानि डिफ़ॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पर हमारे दिशानिर्देशों के मामले में देखा जा सकता है।

हालाँकि, समान स्तर के खेल के मैदान को बनाए रखने के लिए उन नियमों को सुनिश्चित करके संतुलित किया जाना चाहिए जो फर्म द्वारा वित्तीय प्रणाली के लिए उत्पन्न जोखिमों के अनुपात में हों। हम यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति काफी सचेत हैं कि किसी इकाई पर विनियामक बोझ वित्तीय प्रणाली और उसके संचालन के आकार के लिए उत्पन्न जोखिमों के अनुपात में होना चाहिए। इस विचार ने एनबीएफसी के लिए हमारे संशोधित पैमाने-आधारित विनियामक दृष्टिकोण और यूसीबी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे को रेखांकित किया है।

हालाँकि, इसकी भी सराहना की जानी चाहिए कि विनियामक मध्यस्थता की क्षमता को सीमित करना और बाजार सहभागियों के लिए समान अवसर स्थापित करना विनियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन यह सर्वोपरि नहीं है। कुशल बाज़ार कामकाज सुनिश्चित करने के लिए और अधिक व्यापक रूप से, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए, नीति निर्माताओं को, कभी-कभी, विभिन्न सहभागियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

आज की गतिशील और परस्पर जुड़ी दुनिया में विनियमन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिस पर काबू पाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

एक विनियामक के रूप में, समाज में हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि हम अपना काम करते हैं - दूरदर्शी, जोखिम-आधारित और आनुपातिक विनियम बनाकर और उन्हें सुसंगत तरीके से लागू करके। साथ ही, हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि विनियमन बनाने की प्रक्रिया से वित्तीय प्रणाली के लिए शुद्ध अधिशेष प्राप्त होना चाहिए। भले ही हम इन पंक्तियों पर आगे बढ़ रहे हों, हमें स्थिरता बनाए रखने, संवृद्धि को बढ़ावा देने और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण पर दृढ़ रहने की जरूरत है।